इस धरती पर पूर्ण सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है, यहां केवल अवसर हैं।
– डगलस मैकआर्थर, अमेरिकी जनरल

सुरक्षा की समीक्षा

भारतीय पायलट स्मित मच्छार और उन यात्रियों की दुनियाभर में तारीफ हो रही है, जिन्होंने फ्लाई दुबई की फ्लाइट को हादसे से बचाया। इन लोगों की सूझबूझ, हिम्मत और सही समय पर लिए गए फैसलों ने 174 लोगों की जान बचा ली। आशंका व्यक्त की जा रही है कि विमान को हाईजैक करके 9/11 जैसे हमले की कोशिश हो सकती थी। इस्राइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो एक इंटरव्यू में गंभीर आरोप लगाए हैं।


फ्लाई दुबई हादसा

जांच में जल्दबाजी नहीं । विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था। UAE ने घटना की परिस्थितियों और आरोपी के संभावित मकसद की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओमान के आरोपी को-पायलट ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या इस बारे में साजिश पहले से रची गई थी या किसी ने निर्देश दिए थे? हालांकि अभी ये सवाल ही हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

तथ्यों पर फैसला । जिस 9/11 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, उसने वैश्विक राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इस समय भी कमोबेश वैसे ही हालात हैं। विमान का इस्राइल जाना और उसमें ज्यादातर इस्राइली नागरिकों का सवार होना मामले को बेहद संवेदनशील बना देता है। इसलिए सारी बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी गलत आकलन पश्चिम एशिया के हालात को और नाजुक बना सकता है। हां, इस घटना के बाद कॉकपिट की सुरक्षा से जुड़े कुछ बुनियादी पहलुओं को जरूर देखा जाना चाहिए।

भीतर से खतरा । वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने कॉकपिट से जुड़े नियमों को मजबूत किया था। बाद में वह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने भी अपना ली। दुनियाभर के हवाईअड्डों पर सुरक्षा से जुड़े इंतजाम बेहद कड़े होते हैं। लेकिन, ज्यादातर जगह फोकस बाहरी घुसपैठ रोकने पर है। अगर बाहर के बजाय खतरा कॉकपिट से ही हो तो क्या, जैसा इस केस में हुआ? इस्राइल अपने यहां पायलटों की जांच कड़ी करने जा रहा है।

निष्कर्ष से रास्ता । यह बिल्कुल ही असामान्य स्थिति थी, जिसका समाधान भी असामान्य रहा, पर हर बार ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। सुरक्षा उपायों से लेकर इमरजेंसी से निपटने की चालक दल की ट्रेनिंग तक, हो सकता है कि सब पर नए सिरे से विचार करना पड़े। हालांकि सही जवाब जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।

तिराहा

लोकतंत्र का लाउंज

सियासत के गुण सुखनंदन को विरासत में मिले हैं। वह पिता ही क्या जो अपनी विरासत भावी पीढ़ी को न दे! इसलिए वह सुरम्य को भी इसमें दीक्षित कर रहे हैं। पिता-पुत्र का आज का पाठ था, 'उच्च सदन।' हालांकि जिज्ञासा सुधर्मा ने व्यक्त की, 'उच्च सदन का पर्यायवाची क्या है?' 'लोकतंत्र का कॉरपोरेट लाउंज, जहां राजनीति और पूंजी का संगम होता है।' सुखनंदन ने जवाब दिया और सुरम्य से मुखातिब हुए, 'अंग्रेजों का हाउस ऑफ लॉर्ड्स देख नीति नियंताओं ने उच्च सदन अपनाया। लेकिन, आजादी के बाद लॉर्ड खत्म हो गए। सदन की उच्चता तो बरकरार रखनी है। इसलिए भरपाई कभी माई लॉर्ड, कभी लाट साहब तो कभी सोने की लाट वालों को भेजकर की जाती है।' 'उच्च सदन स्थायी क्यों है?' 'क्योंकि विचार, सरकार और हार अस्थाई है, लेकिन पुनर्वास व पूंजी की आवश्यकता स्थायी है। उच्च सदन इनका प्रतिफल है।'


प्रेम शंकर मिश्र



'लेकिन, नेता की सबसे बड़ी पूंजी तो उसके कार्यकर्ता हैं?' सुधर्मा ने बीच में नाराज कार्यकर्ता की तरह टोक दिया। 'इसे जनाधार कहते हैं, जिससे राजनीतिक पूंजी बनती है और फिर उसका नकदीकरण किया जाता है', सुखनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 'कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का प्रतिफल कौन देगा?' स्वर में अब भी नाराजगी थी। 'प्रिये! कार्यकर्ताओं की मेहनत अनमोल है, उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। राजनीति में सबकी भूमिका तय है। नेता के पास शक्ति है, वह सत्ता संभालेगा। सेठ के पास संसाधन हैं, पूंजी संभालेगा। कार्यकर्ता के पास निष्ठा है, वह उम्मीद संभालेगा। जब शक्ति और पूंजी मिलेंगे तो कार्यकर्ता ताली बजाएगा।' तभी नेपथ्य से आवाज आई, 'अध्यक्ष जी! कार्यकर्ता बाहर गेट पर खड़ा है!' 'वह अपनी निर्धारित जगह पर है, तुम गेट बंद कर दो।' अध्यक्ष जी ने जवाब दिया।

यह व्यंग्य आपको कैसा लगा
1 से 5 के स्केल पर रेट करें।
जितना अच्छा, उतने नंबर।
स्कैन करें और वोट दें

एकदा

संकलन : रेनू सैनी

बापू की नींद

महात्मा गांधी घंटों काम करते थे और आराम के लिए कम समय निकालते। एक दिन उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी जरूरी विषय पर चर्चा के लिए बुलाया। मौलाना तय समय से कुछ मिनट पहले पहुंच गए। गांधीजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 'मौलाना साहब, अभी चार-पांच मिनट बाकी हैं। मैं थोड़ा थक गया हूं। अगर आप इजाजत दें तो कुछ देर आराम कर लूं!' मौलाना आजाद ने कहा, 'बापू, आपको वैसे भी आराम का समय कम मिलता है। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए।' गांधीजी वहीं लेट गए और कुछ ही क्षण में गहरी नींद में चले गए। मौलाना यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि दिनभर लोगों से मिलना, समस्याएं सुनना और लगातार काम करना निश्चित ही बहुत थका देने वाला होता होगा। लेकिन, ठीक चार मिनट बाद गांधीजी उठकर बैठ गए और बोले, 'हां मौलाना साहब, अब बताइए। मैं बिल्कुल तैयार हूं।' मौलाना ने आश्चर्य से पूछा, 'बापू, आप तो पलक झपकते ही सो गए और ठीक समय पर अपने आप जाग भी गए!' गांधीजी बोले, 'मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं भी बस उसी का अभ्यास करता हूं।'



गिग इकॉनमी में आय और सुरक्षा सीमित, इसे बेरोज़गारी का समाधान नहीं मान सकते

सिर्फ़ गिग से नहीं बनेगी बात


AI image


सुचिता दत्ता

यह सुनने में अच्छा लगता है कि भारत की बेरोजगारी दर आधिकारिक रूप से 3.2% है। लेकिन, धरातल पर हालात अलग हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2024-25 के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। भले ही 2017-18 के 6.1% के मुकाबले बेरोजगारी अब आधी रह गई है, लेकिन नौकरियों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। कागजी आंकड़े और सच्चाई के बीच इस अंतर का एक कारण गिग इकॉनमी भी है, जहां अस्थायी और कम आमदनी वाले काम भी रोजगार में गिने जाते हैं। गिग इकॉनमी यानी जहां शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉजेक्ट आधारित काम होते हैं।

असलियत से अलग । आप जानिए भारत में नौकरी की गिनती कैसे होती है। PLFS में अगर किसी शख्स ने तय हफ्ते में थोड़ी देर भी काम किया है, तो उसे रोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। पारिवारिक कारोबार में अवैतनिक काम कर रहे लोग भी इसमें आते हैं। यानी नौकरी न मिलने पर कैब चलाने वाला या इंटरव्यू के इंतजार में खाना डिलिवर करने वाला भी नौकरीपेशा माना जाएगा। सर्वे काम की गुणवत्ता नहीं, सिर्फ काम होने को देखता है। इसलिए बेरोजगारी की असल तस्वीर ज्यादा खौफनाक है।

सुरक्षित नौकरी नहीं । भारत के सिर्फ 23.6% लोगों के पास ही नियमित वेतन वाली नौकरी है। 10 में से बमुश्किल एक शख्स के पास कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी है, जबकि तकरीबन 56% लोग सेल्फ-एम्प्लॉयड हैं। नियमित कामगार हर महीने औसतन 22,699 रुपये कमाता है, जबकि सेल्फ-एम्प्लॉयड की 14,861 रुपये और कैजुअल वर्कर की सिर्फ 10,000 रुपये कमाई है। रोजगार बढ़ा है, पर सुरक्षित और अच्छी कमाई वाली नौकरियां नहीं।

AI सारांश

- भारत में बेरोजगारी दर 3.2% तक घटने के बावजूद रोजगार की गुणवत्ता, आय और सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।
- गिग वर्क ने रोजगार के आंकड़े बढ़ाए हैं, लेकिन नियमित वेतन और सुरक्षित नौकरी का हिस्सा सीमित है।
- कम बेरोजगारी के बजाय वेतन, सामाजिक सुरक्षा को रोजगार की सफलता का पैमाना बनाना होगा।

लगातार बढ़ता आंकड़ा । नीति आयोग का अनुमान है कि गिग वर्कफोर्स 2020-21 के 77 लाख से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाएगी। यह लाखों लोगों की आजीविका का बड़ा जरिया है, लेकिन दूसरा पहलू भी है। अध्ययन बताते हैं कि घर-घर सामान पहुंचाने वाले और राइड हेलिंग कंपनियों के ड्राइवर हर महीने 15 से 20 हजार रुपये ही कमाते हैं। अगर उनके काम के घंटों को देखें तो यह न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।

बिना वेतन काम । महिलाओं के लिहाज से तस्वीर और चिंताजनक है। श्रम बल भागीदारी में महिलाओं की तादाद 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गई है, जिसे तरक्की कहा जा सकता है। लेकिन, इस वृद्धि में बड़ा योगदान ग्रामीण महिलाओं के बिना वेतन वाले पारिवारिक काम का है। चार साल में खुद का काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 53.4% से बढ़कर 65.3% हुई, जबकि बिना वेतन वाले पारिवारिक काम की हिस्सेदारी 30.8% से बढ़कर 37.5%। ग्रामीण भारत में अब 40% से ज्यादा कामकाजी महिलाएं ऐसे बिना वेतन वाले काम में मददगार हैं।

समस्या दूसरी । इन बातों का यह अर्थ कतई नहीं है कि गिग इकॉनमी खराब है। इसने लाखों लोगों को कमाई का नया जरिया देने के साथ काम करने की आजादी और युवाओं के लिए नए मौके भी खोले हैं। इसलिए, इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिना सोचे इसकी तारीफ करना भी सही नहीं होगा। असल समस्या तब है जब इसे कम रोजगार की समस्या का पूरा समाधान मान लिया जाए और इसकी बढ़ती संख्या को सबूत समझ लिया जाए कि समस्या खत्म हो गई है।

सफलता का पैमाना । सही रास्ता रोजगार को औपचारिक बनाना है। भारत में इसका ढांचा मौजूद है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 ने पहली बार गिग और प्लैटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान दी और एक्सीडेंट कवर, हेल्थ बेनिफिट और बुढ़ापे की सुरक्षा का रास्ता बनाया। प्लैटफॉर्म वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और औपचारिक पे-रोल से जोड़ना होगा। रोजगार की सफलता भी इसी से मापनी चाहिए।

सही तस्वीर जरूरी । भारत को जनसांख्यिकीय फायदा सिर्फ कम बेरोजगारी दर से नहीं मिलेगा। जब तक काम की सही तस्वीर सामने नहीं आती और उसे बेहतर बनाने के लिए कानून नहीं बनते, 3.2% का आंकड़ा संकट को सिर्फ छिपाएगा।

(लेखिका इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की कार्यकारी निदेशक हैं)

AI जब आपकी ओर से ख़रीदारी करेगी

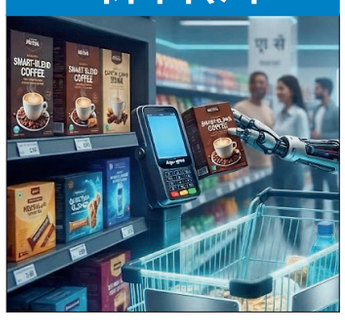

सतीश सिंह

आज हम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) से सवाल पूछते हैं, जानकारियां जुटाते हैं या उत्पादों की कीमतों की तुलना करते हैं, लेकिन भुगतान करने का आखिरी फैसला हमारा होता है। AI के अगले चरण में यह बदल सकता है। एजेंटिक AI लक्ष्य समझकर जरूरी कदम तय करने और हमारी अनुमति से उन्हें पूरा करने में सक्षम होगी। मसलन, 20 हजार रुपये में दिल्ली की यात्रा का पूरा इंतजाम जैसे काम वह खुद कर सकेगी। यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था में मनुष्य की ओर से मशीन ग्राहक बन सकती है।

सेवा में मददगार । भारत में इस परिवर्तन का असर विकसित देशों से अलग और व्यापक हो सकता है। वजह है डिजिटल ढांचा। आधार, UPI, डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर और मोबाइल बैंकिंग ने लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। अब AI एजेंट की परत जुड़ने से भुगतान तरीका बदल सकता है। आज हम भुगतान करते हैं, कल हमारे लिए यह काम AI कर सकती है। बैंकिंग में AI ऋण, बीमा और निवेश विकल्पों की तुलना, जोखिम आकलन, धोखाधड़ी पहचान और ग्राहक सेवा में मदद कर सकती है।

डिजिटल मुनीम । भारत में डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती है। AI इसमें भूमिका निभा सकती है। बैंकिंग लेनदेन के पैटर्न का विश्लेषण कर संदिग्ध व्यवहार पहचाना जा सकता है। RBI इनोवेशन हब के mulehunter.AI जैसे मॉडल इसकी संभावनाएं दिखाते हैं। लेकिन, यही तकनीक अपराधियों के हाथ में पड़ी तो धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाएगा। भविष्य में साइबर सुरक्षा को पासवर्ड और OTP से आगे बढ़ाना होगा।

कॉमनरूम



री-स्किलिंग जरूरी । भारत के लिए AI की परीक्षा यह होगी कि उसका लाभ कंपनियों से आगे छोटे कारोबारियों तक पहुंचे। सस्ती और भारतीय भाषाओं में तकनीक से दुकानदार बिक्री, स्टॉक और प्रचार संभाल सकेंगे। किसान बाजार भाव और मौसम की जानकारी समझ सकेगा। उद्यमी सरकारी योजनाओं, ऋण और अनुपालन की जानकारी पा सकेंगे। इससे उत्पादकता और अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ सकता है। AI से रोजगार पर असर की आशंका है। नियमित काम मशीनों के पास जा सकते हैं, जबकि विश्लेषण, संवाद और निर्णय जैसे कौशलों का महत्व बढ़ेगा। इसलिए री-स्किलिंग जरूरी होगी।

जिम्मेदारी बढ़ेगी । वित्तीय AI को खुली छूट देने के बजाय खर्च की सीमा, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, संवेदनशील लेनदेन में मानवीय स्वीकृति, स्पष्ट ऑडिट ट्रेल और ग्राहक को निर्णय रोकने का अधिकार जैसी सुरक्षा जरूरी होगी। RBI का जिम्मेदार और नैतिक AI उपयोग पर जोर महत्वपूर्ण है। AI से उत्पादकता बढ़ेगी, बैंकिंग अधिक व्यक्तिगत होगी और छोटे कारोबारियों को बड़ी कंपनियों जैसी विश्लेषण क्षमता मिल सकती है। सुविधा बढ़ने पर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

कई बार तैयारी का ही हिस्सा होती है देरी

संजय तेवतिया

जीवन में कभी न कभी हम ऐसे दौर से गुजरते हैं, जब लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा और जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे हमसे दूर होती जा रही हैं। कोई उम्मीद बंधती है, तो हमारे मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार होने में इतनी देर क्यों हो रही? लेकिन हर देरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार वह किसी अनदेखी तैयारी का हिस्सा होती है।

हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा, हमारी गति और हमारे तय समय के अनुसार हो। लेकिन, प्रकृति का अपना समय है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता। उसके भीतर जड़ें फैलती हैं, अंकुर फूटता है और धीरे-धीरे पौधा आकार लेता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना वृक्ष का अस्तित्व संभव नहीं। हमारी प्रार्थनाओं और प्रयासों के साथ भी कुछ ऐसा ही है।


AI Image

इसलिए किसी काम में देर हो तो तुरंत यह न मानें कि सब कुछ गलत हो रहा है। इससे मन में निराशा का भाव पनपता है। संभव है, वह देरी आपको किसी ऐसी परिस्थिति से बचा रही हो, जिसका आपको अभी पता नहीं। हो सकता है, जिस अवसर को आप खोया हुआ समय समझ रहे हैं, वह आपको किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा रहा हो। यह भी संभव है कि जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हैं, उसे संभालने के लिए आपको पहले स्वयं को भीतर से मजबूत करना हो। कभी जो चीज हमें नहीं मिलती है शायद वह हमारे लिए सही ही होती है।

अक्सर हम परिणाम पाने की जल्दी में यह भूल जाते हैं कि तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। समय हमें अनुभव देता है, हमारी समझ बढ़ाता है और धैर्य सिखाता है। जब सही अवसर आता है, तब हम उसे पहचानने और उसका उचित उपयोग करने के लिए पहले से अधिक सक्षम होते हैं। देरी विश्वास की भी परीक्षा लेती है, लेकिन इसका अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। हमें अपना कर्म करते रहना है, जिम्मेदारियां निभानी हैं और पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है। देरी का अर्थ हमेशा 'नहीं' नहीं होता। कभी-कभी उसका अर्थ होता है- अभी नहीं, सही समय पर।

कांटे की बात

मुझे लगता है कि बल्ले और गेंद के बीच थोड़ा अधिक मुकाबला होना चाहिए। यह क्रिकेट नहीं, यह सिर्फ बल्लेबाजी है। एक वनडे में 800 से अधिक रन बनना दर्शकों के लिए रोमांचक हो सकता है। लेकिन, असमान मुकाबले से गेंदबाज दर्शक बन जाते हैं।


गौतम गंभीर, *भारतीय क्रिकेट टीम के कोच*

समाज की शख़्सियत

यूट्यूब से सीखकर शह-मात में बनाया इतिहास

भारतीय मूल की बोधना शिवानंदन केवल 11 बरस की उम्र में वुमन ग्रैंडमास्टर बन गई हैं। उन्होंने पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए चेस ओलिंपियाड में इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए यह खिताब जीता। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं।

कोविड में हुई शुरुआत

लंदन में रहने वाली बोधना ने कोविड के दौरान घर में ही शतरंज खेलना शुरू किया था। तब उनके पिता के एक दोस्त भारत लौट रहे थे और उन्होंने अपना कुछ सामान उनके घर पर रखा था। उन्ही सामान में बोधना को चेस बोर्ड मिला। वहीं से शतरंज खेलने की उनकी शुरुआत हुई। पहले तो उन्होंने यूट्यूब पर चेस के विडियो देखकर इस खेल को समझा।



सबसे कम उम्र की चैंपियन

बोधना ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बनी। उन्होंने रैपिड प्लेऑफ में ट्रिशा कन्यामाराला को हराकर खिताब जीता। इससे पहले वह यूनाइटेड किंगडम ओपन विमंस ब्लिट्ज चैंपियन और ब्रिटिश विमंस रैपिड की संयुक्त विजेता भी रह चुकी है। इस साल अप्रैल में वह शतरंज में ब्रिटेन की नंबर एक महिला खिलाड़ी बनी थी और दुनिया की शीर्ष 100 महिला खिलाड़ियों में भी अपनी जगह पक्की की।

*प्रस्तुति : **अभिषेक मिश्र***

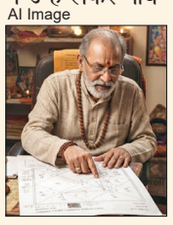
जनता जंक्शन — इरफ़ान



विशुद्ध राजनीति — पॉलिटॉक

8 साल का राजयोग

दक्षिण भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री के ज्योतिषी ने उन्हें लेकर भविष्यवाणी की। उस भविष्यवाणी के आधार पर अब सीएम साहब अपने सियासी सफर के बारे में बात भी करने लगे हैं। एक अनौपचारिक बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि वह कितने साल तक इस पद पर रहेंगे, तो उन्होंने बताया कि उनके ज्योतिषी ने उनके आठ साल तक सीएम रहने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने भी इस भविष्यवाणी के हिसाब से सियासी गणित बैठा लिया है। उनका कहना है कि अभी पहली बार सीएम बनने के बाद उन्हें दो साल का कार्यकाल मिला है। अगले विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी को जिताकर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वह इस जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस हिसाब से तो एक साल फिर भी बच रहा है 8 साल पूरे होने में, तब उन्होंने कहा कि उसके बाद के चुनाव में भी उतरेंगे और एक साल मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर केंद्र की राजनीति का रुख करेंगे। सीएम का प्लान तो पूरा तैयार है, अब देखना होगा कि ज्योतिषी की गणना और सियासी हकीकत एक जैसी होती है या फिर सियासी चाल ज्योतिष गणना की चाल बदलती है।


AI Image

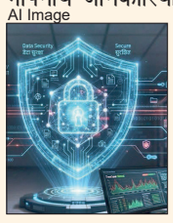
सिर्फ लेख या धरना भी



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपने चुटीले अंदाज में पार्टी के नेताओं की खिंचाई करने का मौका नहीं छोड़ते। मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा के दौरान पार्टी के एक जाने माने और लगातार चर्चाओं में रहने वाले सांसद ने सुझाव दिया कि गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को प्रदर्शन किया जाना चाहिए और धरना देना चाहिए। इस पर खरगे ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप भी धरने में शामिल हो जाइएगा, कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेजी अखबारों में लेख ही लिखते रह जाएं। खरगे की इस टिप्पणी पर बैठक में मौजूद कई नेता मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वैसे यह पहली बार नहीं है जब खरगे ने इन सांसद पर तंज कसा हो। इससे पहले I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक में भी उन्होंने सांसद के मीडिया में सक्रिय रहने पर सवाल उठाते हुए हल्द्वानी के शुद्धीकरण विवाद पर उनकी चुप्पी को लेकर टिप्पणी की थी।

कैसे लीक हो रही सूचनाएं

केंद्र के कुछ मंत्रालयों से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां कौन लीक कर रहा है? दबी जुबान में यह सवाल इन दिनों मंत्रालयों के गलियारों में चल रहा है। एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि सूचनाएं किस स्तर से बाहर जा रही हैं। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि लीक जानबूझकर हुआ या किसी सुरक्षा चूक के कारण या फिर डिजिटल सिस्टम में सेंध लग गई है। शुरुआती फोकस किसी एक शख्स को चिह्नित करने के बजाय सूचना के स्रोत, उसे हासिल करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और उसके बाहर पहुंचने के पूरे चैनल की जांच पर है। संवेदनशील सूचनाओं की लीकेज को रोकने के लिए मंत्रालयों और सुरक्षा से जुड़े तंत्र में इंटरनल कम्यूनिकेशन व डेटा-सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा की जा रही है। सरकार पहले भी मंत्रालयों के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरनल कम्यूनिकेशन और सख्त सुरक्षा पर जोर देती रही है। नतीजतन मंत्रालय से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी इन दिनों फोन पर किसी भी तरह की बात करने से कतरा रहे हैं।

AI Image


रीडर्स मेल

सभी की जिम्मेदारी

1 अक्टूबर का संपादकीय 'बीच का रास्ता' पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं है, क्योंकि इस उद्योग से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है। हालांकि, स्वास्थ्य और प्रदूषण से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली जैसे शहरों में दीपावली पर हवा जहरीली हो जाती है, जो सांस के मरीजों के लिए घातक है। इसलिए, एकतरफा बैन के बजाय अवैध निर्माण रोककर ग्रीन पटाखों के उपयोग को बढ़ावा देना और तय नियमों का पालन कराना ही एक व्यावहारिक और सही समाधान है। नागरिकों को भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा, तब ही हम परंपरा और सेहत की रक्षा कर सकेंगे।

राजेश बंसल, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। यह समाचार पत्र स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित, आशीष पांडे द्वारा संपादित (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी) तथा मनीष सिन्हा द्वारा, **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, 13/1 & 2, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र.)** से और नवनीत आहूजा द्वारा, प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर-11, IMT मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 से मुद्रित। फोन : 23302000, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.